SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a natural calamity. The Natural Calamity Commission should look after this. They should take care of these poor people, and crop insurance should be implemented immediately.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI N.R. GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

Strike by Central University Teachers

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): महोदया, आज 15 दिसम्बर से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार उनका वेतनमान भी निर्धारित किया जाना चाहिए और भुगतान किया जाना चाहिए। यह हड़ताल बहुत गहरे परिणाम रखती है, क्योंकि इससे छात्रों तथा उनके अभिभावकों के भविष्य जुड़े हुए हैं। अभी तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हड़ताल है, फिर यह हड़ताल राज्यों के विश्वविद्यालयों में जाएगी, कॉलेजेज़ में जाएगी। एक अनावश्यक बात पर इस हड़ताल को रोका जा सकता था, वह रोका नहीं गया है। यह काम यूजीसी को दिया जाता है कि वह इनके वेतनमानों का शीघ्र निर्धारण करके निश्चित करे। उन्होंने एक चड्ढा कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट का भी क्या हुआ, सरकार ने क्या दृष्टिकोण लिया, उसमें क्या खामियां हैं, क्या नहीं हैं, इसके बारे में भी न तो सदन को बताया गया है, न देश को बताया गया है। अध्यापकों में घोर असंतोष है। मैं यह चाहूंगा और शायद सदन इस मामले में एक राय होगा कि अध्यापकों की हड़ताल को रोका जाए और उनके वेतनमान ठीक से दुरुस्त करके दिए जाएं। यह बात कि केवल आईएएस अधिकारी अध्यापकों से अधिक तनख्वाह पाते रहें और अध्यापक की तनख्वाह उनसे बढ़ न जाए, यह निर्धारण का मानदण्ड नहीं होना चाहिए। अध्यापकों के वेतनमान दुनिया में अनेक स्थानों पर अधिक है।

SHRIMATI JAYA BACHCNAN (Uttar Pradesh): Madam, Ministers are talking while he is speaking. We can't listen to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Can we have order please?

डा. मुरली मनोहर जोशी: इस समय शिक्षा मंत्री महोदय बहुत गंभीर वार्तालाप में व्यस्त हैं। इसी से जाहिर होता है कि अध्यापकों के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या दृष्टिकोण है। महोदया, मैं चाहूंगा कि आप कम-से-कम शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करें कि वे सदन में अध्यापकों पर चर्चा की तरफ ध्यान दें, न कि आपस में गंभीर चर्चा पर। मैं जानता हूं कि जाबिर हुसैन साहब बहुत बड़े साहित्यकार हैं और मंत्री महोदय उन्हीं के राज्य से आते हैं, लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक आपकी जिम्मेदारी हैं, जो आज हड़ताल पर गए हैं। मैं जानना

चाहूंगा कि सरकार उन हड़तालियों को क्या आश्वासन दे रही है और उस हड़ताल को कैसे रोकना चाहती है? यह हड़ताल देशव्यापी है और यह राजकीय विद्यालयों में भी और राज्य के विश्वविद्यालयों में भी हो जाएगी। बिहार प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा और यह एक गम्भीर रूप धारण कर सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस बारे में तत्काल निर्णय लिया जाए तथा इस हड़ताल को रोका जाए, छात्रों का भविष्य संभाला जाए और देश को होने वाली हानि से देश को बचाया जाए। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, कृपया इस पर शीघ्र अपनी प्रतिक्रिया दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): महोदया, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा उठाए गए इस विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा उठाए गए इस विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Madam, I associate myself with the matter raised by Dr. Murli Manohar Joshi.

Demand to clear pending cases of pension to freedom fighters of Goa

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Madam, Goa is celebrating its 47th year of independence on 19th December 2008. We became liberated after 450 years of Portuguese rule. But, Madam, unfortunately, hundreds of cases of freedom fighters from Goa are pending in the Home Ministry and they are being scrutinised at very slow pace. It is possible that scrutiny of documents can take time. But, Madam, it is seen that after an application is made, some officers will apply their mind, after about a year or so, to the application. Thereafter, in writing to the freedom fighter, they will take another one year. If a clarification is issued, to examine that clarification or requiring additional documents, they take another few months. In such a manner, Madam, it takes years together to scrutinise a simple application regarding freedom fighters.

Now, Madam, in the present circumstances, when we have got the electronic medium, there is a way out that if any document is not missing, the State Government can be contacted and the State Government can, in turn, contact the concerned freedom fighter and obtain the necessary information and thereafter, the documents can be examined and the information can be scrutinised and speedy justice can be given to the freedom fighters. Second option, Madam, is this that Lok Adalats can be held in all the States wherever applications of freedom fighters are pending and the officer concerned can come for 2-3 days in the State Capitals or if there are many applications, in some districts and can call the freedom fighters, have interaction with them, find out the documents which are lacking, take information from them and dispose of the matter. In case some applications are remaining where documents required need time, then, they can be given further time and they can go to the State Capitals and the documents can be sent. In this manner, disposal of freedom fighters' applications can be done speedily.

Therefore, Madam, I request the Home Ministry to establish Lok Adalats for the disposal of freedom fighters cases from Goa.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Shrimati Jaya Bachchan will associate. We don't normally speak on them.